भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3228
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में पेयजल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण

3228. श्री डी. एम. कथीर आनंदः
डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि होगेनक्कल एकीकृत पेयजल परियोजना, चरण-III केंद्र सरकार के 2,283 करोड़ रुपये के हिस्से को जारी न किए जाने के कारण धीमी गति से चल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लंबित धनराशि जारी करने में तेजी लाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) वेल्लोर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में किसी भी पेयजल परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्ष की अवधि अर्थात 2019-20 से 2023-24 के लिए जेजेएम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, जिसके दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन को पूरा करना अपेक्षित था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सूचित किया गया कि जेजेएम के तहत केंद्रीय सहायता केवल मिशन अवधि के दौरान उठाए गए निधि लाभ तक सीमित रहेगी।

तमिलनाडु सरकार की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने जून 2023 में होगेनक्कल जल आपूर्ति परियोजना, चरण-III को मंजूरी दी; तथापि, इस परियोजना को मिशन अवधि के भीतर अवार्ड नहीं किया जा सका।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

(ग): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर एक साथ कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का परियोजना-वार ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर रखा जाता है।

मिशन अवधि के दौरान, वेल्लोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए विभिन्न ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु को 5,899.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

*****